



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 11, 2017/आश्विन 19, 1939

No. 394]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 11, 2017/ASVINA 19, 1939

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 29 सितम्बर, 2017

**सं.-टीएमपी/60/2017-सीएचपीटी.**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा चेन्नई पत्तन न्यास में कार्गो प्रहस्तन प्रचालनों के लिए 100 टन चल हार्बर क्रेनों (एचएमसी) की आपूर्ति, प्रचालन और अनुरक्षण के दरमानों की अधिसूचना के लिए मैसर्ज ग्लोबल पोर्ट साल्यूशनज प्रा. लि. (जीपीएसपीएल) से प्राप्त प्रस्ताव का इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, निपटान करता है।

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

### मामला संख्या टीएमपी/60/2017-सीएचपीटी

मैसर्ज ग्लोबल पोर्ट साल्यूशनज प्रा. लि.

..... आवेदक

## गणपूर्ति

- (i) श्री टी.एस.बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

## आदेश

(सितम्बर, 2017 के 15 वें दिन पारित)

चेन्नई पत्तन न्यास में कार्गो प्रहस्तन प्रचालनों के लिए 100 टन हार्बर क्रेनों (एचएमसी) की आपूर्ति, प्रचालन और अनुरक्षण के दरमानों की अधिसूचना के लिए मैसर्ज ग्लोबल पोर्ट साल्यूशनज प्रा. लि. (जीपीएसपीएल) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

- 2.1 सीएचपीटी द्वारा सीएचपीटी की बर्थ संख्या डब्ल्यू क्यू -I, ii, iii व iv तथा मध्य बर्थ एसक्यू I और II जेडी-I, जेडी-II और जेडी v पर एचएमसी की आपूर्ति अनुरक्षण और प्रचालन के आधार पर, इस प्राधिकरण ने 30 जून, 2014 के अपने आदेश सं. टीएमपी/20/2014-सीएचपीटी के द्वारा प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2013 के अंतर्गत संदर्भ दरमान अनुमोदित किए थे।
- 2.2 महापत्तन न्यास (एमपीटी) अधिनियम, 1963 की धारा 42(4) के साथ पठित धारा 48 के अनुसार महापत्तन न्यास द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित दरमानों के आधार पर ऐसे अधिकृत व्यक्ति के नाम से, प्रशुल्कों की उगाही कर सकता है।
- 3.1 सीएचपीटी के साथ, किसी अन्य मामलों में, पत्र व्यवहार के दौरान हमने पाया कि सीएचपीटी ने किसी अन्य प्रचालक को सीएचपीटी पर सेवाएं प्रदान करने के लिए पहले से ही प्राधिकृत कर रखा है। उक्त प्रचालक ने अपने नाम से दरमानों की अधिसूचना के लिए इस प्राधिकरण को सम्पर्क नहीं किया है। तदनुसार, सीएचपीटी (लाइसेंस धारक के नाते) हमने 7 जून, 2017 को अपने पत्र सं. टीएमपी/52/2017-सीएचपीटी द्वारा अनुरोध किया कि संबंधित प्रचालक को अपने नाम से दरमानों की अधिसूचना के लिए इस प्राधिकरण के समक्ष उपयुक्त प्रस्ताव रखें।
- 3.2 सीएचपीटी ने 20 जून, 2017 के अपने पत्र सं. एमईई/एमआई/024/2014-डि.सी.एमई (आरएंडडी) के द्वारा में मैसर्स ग्लोबल पोर्ट सल्यूशन्स प्रा. लि. (जीपीएसपीएल) अपने नाम से दरमानों की अधिसूचना के लिए एक प्रस्ताव दायर करने को कहा।
- 3.3 प्रत्युत्तर में, जीपीएसपीएल ने अपने 22 जून, 2017 के पत्र के द्वारा प्राधिकरण को सीएचपीटी स्थित चल हार्बर क्रेन की आपूर्ति, प्रचालन और अनुरक्षण की दरमानों के संशोधन का शीघ्रता से करने का अनुरोध किया क्योंकि चालू वित्तीय वर्ष के 3 महीने पहले ही गुजर चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दरों के संशोधन में किसी विलम्ब से उन्हें भारी वित्तीय भार झेलना पड़ सकता है और वे कार्य के पूरा होने और बिलिंग के पश्चात अतिरिक्त प्रशुल्क की उगाही, यदि कोई हो, की स्थिति में नहीं है।
- 3.4 तत्पश्चात, जीपीएसपीएल ने अपने 11 जुलाई, 2017 के पत्र के द्वारा निम्नलिखित निवेदन रखे :
- दिए गए आदेश के अनुसार, ग्राही एमएचसी तैनात करने के लिए प्रभारों को अन्य पत्तन प्रभारों की तरह अग्रिम में एकत्र कर लेता है, जो अन्य महापत्तनों में एक नियमित प्रथा है।
  - तथापि, जीपीएसपीएल ग्राहकों से एमएचसी प्रभार वसूल करने में दिक्कतों का सामना कर रहा है और सीएचपीटी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता।
  - यह मामला सार्वजनिक निजी भागीदारी स्कीम के अंतर्गत सीएचपीटी और जीपीएसपीएल के बीच हुए करार के अनुरूप है।
  - इसके अतिरिक्त, जीपीएसपीएल करार के अनुसार विलम्बित पत्तन राजस्व हिस्से पर ब्याज (बैंक दर + 2 प्रतिशत) का भुगतान करता है।
  - यह अनुरोध किया जाता है कि वर्ष 2017-18 के लिए एचएमसी प्रभारों के संशोधित दरमान जारी करें।
- 3.5. इसके अतिरिक्त, जीपीएसपीएल ने अपने 18 जुलाई, 2017 के ईमेल के द्वारा बताया कि जीपीएसपीएल ने सीएचपीटी के विरुद्ध आबंटित बर्थों के विषय में एक पंचाट दायर किया हुआ है और अंतरिम पंचाट आदेश के अनुसार जीपीएसपीएल को जेडी 2, 4 और 6 में कार्गो प्रहस्तन की अनुज्ञा दी गई है।
- 4.1. जीपीएसपीएल ने जून, 2014 में संदर्भ, प्रशुल्क आदेश में अधिसूचित दरों को प्रस्तावित दरों की उगाही को शासी करने वाली सोपाधिकताओं के साथ पूरे प्रारूप दरमान, अपने नाम से अधिसूचित करने का प्रस्ताव, प्रस्तुत नहीं किया है। जीपीएसपीएल ने स्वतंत्र इंजीनियर से समापन प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। तदनुसार, हमने 28 जुलाई, 2017 के अपने पत्र के द्वारा जीपीएसपीएल को दरमानों और शासी सोपाधिकताओं और स्वतंत्र इंजीनियर से परियोजना के समापन प्रमाणपत्र की प्रति के साथ पूरा प्रस्ताव हमें और लाइसेंसदाता पत्तन सीएचपीटी को प्रस्तुत करें।

- 4.2. साथ ही साथ 28 जुलाई, 2017 के अपने पत्र के द्वारा सीएचपीटी को भी अनुरोध किया कि वह जीपीएसपीएल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना / दस्तावेजों पर अपनी टिप्पणी हमें भेजें। जीपीएसपीएल के 18 जुलाई, 2017 के ई-मेल की एक प्रति सीएचपीटी को भी उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी। लेकिन, सीएचपीटी ने मामले की अंतिमता तक उत्तर नहीं दिया।
- 5.1. 28 जुलाई, 2017 के हमारे पत्र के प्रत्युत्तर में जीपीएसपीएल ने अपने 1 अगस्त, 2017 के ईमेल के द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए :
- सीएचपीटी में 100 टन हार्बर क्रेनों की आपूर्ति, प्रचालन और अनुरक्षण की निविदा रोडविंग इंटरनैशनल प्राइवेट लिमिटेड और अपना लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के एक संघ को दी गई थी जिन्होंने ग्लोबल पोर्ट साल्यूशनज प्राइवेट लिमिटेड नामक एक विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) का गठन किया।
  - सीएचपीटी से पहले प्राप्त एक पत्र के आधार पर प्राधिकरण के 8 अप्रैल, 2015 के पत्र के अनुसार दरों का 2.29 प्रतिशत पर सूचकांकन किया गया।
  - जीपीएसपीएल द्वारा 2.29 प्रतिशत के सूचकांक के साथ अब तक दरों की उगाही की जा रही है, जैसा नीचे दिया गया है :

सीएचपीटी पर 100 टन मोबाइल क्रेन के प्रयोग के लिए प्रति टन प्रहस्तन प्रभार:

क्र.सं.	कार्गो की किस्म	विदेशी रु.	तटीय रु.
1	शुष्क बल्क कार्गो	47.91	28.74
2	स्टील और बोराबंद कार्गो	99.81	59.89
3	अन्य ब्रेक बल्क कार्गो	159.69	95.82

सीएचपीटी में 100 टन चल क्रेन को प्रयोग पर प्रति टन विविध प्रभार :

क्र.सं.	कार्गो की किस्म	विदेशी रु.	तटीय रु.
1	शुष्क बल्क कार्गो	0.98	0.58
2	स्टील और बोराबंद कार्गो	2.04	1.22
3	अन्य ब्रेक बल्क कार्गो	3.26	1.95

- हार्बर क्रेनों के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के आधार पर दरमानों के सूचकांकन का जीपीएसपीएल के नाम में करने का अनुरोध किया जाता है।
- 5.2. जीपीएसपीएल ने सीएचपीटी द्वारा जारी प्रवर्तन प्रमाणपत्र की एक प्रति और परियोजना के लिए दरमानों की प्रति भी भेजी है। सीएचपीटी द्वारा जारी प्रमाणपत्र बताता है कि 15 जून, 2015 को 2 नग चल हार्बर क्रेन आरंभ की गई थी और क्रेन व्यापार सूचना जारी किए जाने के पश्चात, 22 जून, 2015 से प्रचालन में आई।
6. मामले का परीक्षण जीपीएसपीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर किया गया।
- 7.1. अप्रेंट प्रशुल्क निर्धारण के लिए प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 का खंड 2.9.1 अनुबद्ध करता है कि प्राइवेट प्रचालक एमपीटी की धारा 48 में यथापेक्षित वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करने से पूर्व अपने प्रचालनों पर लागू अधिकतम दरों के साथ दरमानों की अधिसूचना के लिए इस प्राधिकरण को संपर्क करेगा। प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2008 के खंड 2.9.2 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने वाले दरमान पत्तन में निर्धारित प्रशुल्क के अनुरूप होने चाहिए और बोली दस्तावेजों में शामिल होने चाहिए और

खंड 2.8 में स्पष्ट किए गए सूचकांकन के अधीन होंगे। ऐसे दरमान निबंधनों का विवरण इस प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा, जैसा कि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में अपेक्षित है।

- 7.2. जबकि अप्रैल प्रशुलक दिशानिर्देश 2008 का खंड 2.9.1 स्पष्ट रूप से अनुवद्ध करता है कि वाणिज्य प्रचालन आरंभ करने से पूर्व, निजी प्रचालक दरमानों की अधिसूचना के लिए इस प्राधिकरण को सम्पर्क करेगा जैसा कि महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 48 में अपेक्षित है, ऐसा उपबंध प्रशुलक दिशानिर्देश 2013 में उपलब्ध नहीं है।
- 7.3. महापत्तन न्यास (एमपीटी) अधिनियम, 1963 की धारा 42(4) के साथ पठित धारा 48 के अनुसार महापत्तन न्यास द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित दरमानों के आधार पर प्रशुलकों की उगाही कर सकता है। ऐसा होने पर, बीओटी प्रचालक, जिसे महापत्तन न्यास द्वारा एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 42 (3) के अंतर्गत अधिकृत किया गया है, प्रशुलक दिशानिर्देश 2013 द्वारा शासित होता है और उसे प्रचालन आरंभ करने से पूर्व सूचकांकित दरमानों को अपने नाम से अधिसूचित कराने की आवश्यकता है।
- 7.4. संदर्भ प्रशुलक दिशानिर्देश, 2013 के खंड 4.2 के अनुसार प्रशुलक धारिता मुद्रास्फिति के प्रति सूचकांकित होती है परंतु 1 जनवरी, 2008 और संबंधित वर्ष की 1 जनवरी के बीच थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में परिवर्तन के 60 प्रतिशत की सीमा तक और इस प्रकार समायोजित प्रशुलक संबंधित वर्ष के 1 अप्रैल से लागू होंगे और आगामी वर्ष की 31 मार्च तक लागू रहेंगे।
- 7.5. इस प्राधिकरण के 30 जून, 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/20/2014-सीएचपीटी द्वारा अनुमोदित चेन्नई पत्तन न्यास की बर्थ संख्या डब्ल्यूक्यू I, II, III, व IV और मध्य बर्थ संख्या एसक्यू I और II, जेडी I, जेडी III और जेडी V पर चल हार्बन क्रेनों के प्रचालन के संदर्भ प्रशुलक के खंड 3 (अनुसूची (2) की सामान्य टिप्पणी) के अनुसार प्रशुलक धारिता 1 जनवरी, 2014 और संबंधित वर्ष की 1 जनवरी, के बीच होने वाले थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के 60 प्रतिशत की हद तक मुद्रास्फिति सूचकांकन होगा।
- 7.6. इस प्राधिकरण द्वारा संदर्भ प्रशुलक का आधार वर्ष और वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए घोषित समतुल्य वार्षिक वृद्धि सीएचपीटी सहित सभी महापत्तन न्यासों को संसूचित की गई थी। तदनुसार इस प्राधिकरण द्वारा घोषित वार्षिक सूचकांकन कारक निम्नवत है :

वर्ष	वार्षिक सूचकांकन कारक
2014-15	3.78 %
2015-16	2.29 %
2016-17	शून्य
2017-18	1.20 %

- 7.7. इस प्रकार, संक्षेप में जीपीएसपीएल अपने नाम से दरमानों की अधिसूचनाओं के लिए 22 जून, 2015 को वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ करने के पश्चात आया है।
8. मामले की संक्रिया के दौरान एकत्र सूचना की समग्रता के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति उभरकर सामने आई है:
- (i) इस प्राधिकरण द्वारा सीएचपीटी द्वारा सीएचपीटी की बर्थ संख्या डब्ल्यूक्यू -I, II, III व IV तथा मध्य बर्थ एसक्यू I और II जेडी-I, जेडी-III और जेडी V पर एचएमसी की आपूर्ति अनुरक्षण और प्रचालन के आधार पर, इस प्राधिकरण ने 30 जून, 2014 के अपने आदेश सं. टीएएमपी/20/2014-सीएचपीटी के द्वारा पारित किया था। उक्त आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण (भाग 3 खंड 4) में 31 जुलाई, 2014 के राजपत्र संख्या 230 में अधिसूचित किया गया था।

- (ii) सीएचपीटी ने चेन्नई पत्तन न्यास की बर्थ संख्या डब्ल्यूक्यू I, II, III, व IV और मध्य बर्थ संख्या एसक्यू I और 2, जेडी 1, जेडी III और जेडी V में 100 टन हार्बर क्रेनों की आपूर्ति, प्रचालन और अनुरक्षण की परियोजना रोडविंग इंटरनैशनल प्राइवेट लिमिटेड और अपना लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के एक संघ को दी गई थी जिन्होंने ग्लोबल पोर्ट साल्यूशनज प्रा. लि. नामक एक विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) का गठन किया। सीएचपीटी ने 31 अगस्त, 2015 को 10 वर्ष की अवधि के लिए जीपीएसपीएल से एक करार किया।
- (iii) जैसा पहले बताया गया है महापत्तन न्यास (एमपीटी) अधिनियम, 1963 की धारा 42(4) के साथ पठित धारा 48 के अनुसार महापत्तन न्यास द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लागू किये जाने वाले दरमान इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किये जाने अपेक्षित हैं। ऐसा होने पर, बीओटी प्रचालक, जिसे महापत्तन न्यास द्वारा एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 42 (3) के अंतर्गत अधिकृत किया गया है, प्रशुल्क दिशानिर्देश 2013 द्वारा शासित होता है और उसे प्रचालन आरंभ करने से पूर्व सूचकांकित दरमानों को अपने नाम से अधिसूचित कराने की आवश्यकता है। जीपीएसपीएल ने दरमानों को, यद्यपि उसने 22 जून, 2015 को अपना वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ करने के पश्चात, अपने नाम से अधिसूचित कराने के अनुरोध के साथ इस प्राधिकरण को सम्पर्क किया है।
- (iv) जीपीएसपीएल ने हमारे साथ हुए विभिन्न पत्रों के आदान प्रदान में उनके नाम से दरों की अधिसूचित करने की तात्कालिता दर्शायी है हो सकता है, उनका यह संकेत हो कि जीपीएसपीएल के नाम से दरमानों को अधिसूचित करने में इस प्राधिकरण की ओर से विलम्ब किया जा रहा हो। इस संबंध में यह उल्लेख करना है कि, जून, 2014 का आदेश पारित होने के पश्चात, लाइसेंस धारक पत्तन सीएचपीटी ने जीपीएसपीएल के साथ रियायत करार किया। जून, 2015 में प्रचालन आरंभ करने से पूर्व जीपीएसपीएल को, सांविधिक उपबंधों को ध्यान में रखकर, दरमान अपने नाम से अधिसूचित कराने के लिए इस प्राधिकरण को सम्पर्क करना चाहिए था। इस प्राधिकरण को भी पहले इसकी जानकारी नहीं थी कि सीएचपीटी ने एचएमसी परिचालनों के लिए जीपीएसपीएल के साथ रियायत करार किया है। तथापि, हमारे ध्यान में मामले आने के तत्काल पश्चात इस दिशा में कदम उठाए कि दरमानों की अधिसूचना जीपीएसपीएल के नाम से हो जाए।
- (v) यद्यपि सीएचपीटी ने जीपीएसपीएल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रति पर कोई उत्तर नहीं दिया है, यह देखा जाता है कि सीएचपीटी ने जीपीएसपीएल को सूचित किया है कि 2 नग एचएमसी को 15 जून, 2015 को चालू किया गया है, और क्रेनों का प्रचालन 22 जून, 2015 से आरंभ हुआ है। सीएचपीटी और जीपीएसपीएल के बीच हुए रियायत करार, जैसा कि सीएचपीटी ने पहले भेजा है, में परियोजना की समाप्ति पर स्वतंत्र इंजीनियर के प्रमाणपत्र जारी करने का उल्लेख नहीं किया है। रियायत करार के अनुसार, ग्राही सीएचपीटी पर दो नग एचएमसी सीएचपीटी में लाया और क्रेने परिचालन के लिए तैयार थी। जीपीएसपीएल ने किसी तृतीय पक्ष द्वारा मई, 2015 में जारी 2 नग एचएमसी आरंभ करने संबंधी रिपोर्ट उपलब्ध करायी है जो क्रेनों की स्थिरता को आशवासित करती है। तदनुसार प्रशुल्क की प्रभावी तारीख 22 जून, 2015 समझी जाती है।

यह देखा गया है कि जीपीएसपीएल ने अपने प्रस्ताव में दरमानों की अधिसूचना की वांछा प्रकट की है परंतु उसने दरमानों के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख का उल्लेख नहीं किया है। यदि संदर्भ प्रशुल्क 1 अप्रैल, 2017 से अधिसूचित किए जाते हैं तो 22 जून, 2015 से 1 अप्रैल, 2017 तक जीपीएसपीएल द्वारा वसूले गए प्रशुल्क को इस प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त नहीं होगा। संविधि के अनुसार, पत्तन द्वारा प्राधिकृत परिचालक इस प्राधिकरण द्वारा दरमानों की अधिसूचना पर ही प्रदत्त सेवाओं के लिए प्रशुल्क की वसूली कर सकता है। जीपीएसपीएल ने जून, 2015 में इस प्राधिकरण से संपर्क नहीं किया कि दरमान उनके नाम से अधिसूचित किए जाए। सीएचपीटी के 9 जून, 2015 के पत्र सं. एमईई/एम/0214/2014/डिजीएमई (आरएंडडी) के अनुसार जिसकी एक प्रति जीपीएसपीएल द्वारा अपने 1 अगस्त, 2017 के ई-मेल में उपलब्ध करायी गई है, सीएचपीटी ने जीपीएसपीएल को सूचकांकित दरमान संसूचित किए हैं।

अब अगस्त, 2017 में जीपीएसपीएल ने अपने नाम से दरमानों की अधिसूचना के लिए प्रस्तावित दरमानों के साथ पूरा प्रस्ताव भेजा है। चूंकि सीएचपीटी ने प्रमाणित किया है कि एचएमसी को प्रचालन के लिए 22 जून, 2015 को प्रयोग में लाया गया है इसलिए प्रभावी तारीख 22 जून, 2015 पर ही विचार किया जाना उपयुक्त समझा जाता है। यह प्राधिकरण 30 जून, 2014 के आदेश में अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क को आधार मानते हुए, इस प्राधिकरण द्वारा जारी डब्ल्यूपीआई वृद्धि लागू करने के अधीन, दरमानों की अधिसूचना के लिए जीपीएसपीएल के प्रस्ताव पर विचार करने को प्रवृत्त है।

- (vi) (क). 30 जून, 2014 के आदेश द्वारा निर्धारित संदर्भ प्रशुल्क के सूचकांकन के संदर्भ में यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि इस प्राधिकरण द्वारा 30 जून, 2014 को पारित संदर्भ प्रशुल्क आदेश संख्या टीएएमपी/20/2014-सीएचपीटी का पैरा 10.1 और संदर्भ प्रशुल्क अनुमोदित करते हुए दरमानों में सामान्य टिप्पणी संख्या 4 बताती है कि प्रशुल्क धारिता 1 जनवरी, 2014 और संबंधित वर्ष की 1 जनवरी, के बीच होने वाले थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के 60 प्रतिशत की हद तक मुद्रास्फिति सूचकांकन होगा। सामान्य टिप्पणी स्पष्ट रूप से बताती है कि डब्ल्यूपीआई वृद्धि के लिए आधार वर्ष 1 जनवरी, 2014 है।

- (ख) 22 जून, 2015 को सूचकांकित दरमान निकालने के लिए 2014 के आधार प्रशुल्क पर लागू वृद्धि कारक 2.29 प्रतिशत है। उक्त सूचकांक और अधिसूचित दरमान 22 जून, 2015 से वर्ष 2015-16 के लिए लागू होंगे। बाद के वर्षों के लिए भी, उक्त प्रशुल्क इस प्राधिकरण द्वारा प्रति वर्ष घोषित किये जाने वाले डब्ल्यूपीआई के 60 प्रतिशत की हद तक वार्षिक स्वतः सूचकांकित होगा। प्रस्तावित दरमानों की धारित सामान्य टिप्पणी संख्या 4 को 30 जून, 2014 के आदेश में अनुमोदित सामान्य टिप्पणी को स्थिति स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त रूप से आशोधित किया जाता है।

इस प्रकार, संक्षेप में, वर्ष 2016-17 और उसके आगे के लिए इस प्राधिकरण के 30 जून, 2014 के आदेश में अनुमोदित दरमानों की सामान्य टिप्पणी 4 में प्रत्येक वर्ष प्रशुल्क कैप में स्वतः प्रशुल्क समंजन निर्धारित किया गया है और समंजित प्रशुल्क कैप संगत वर्ष की 1 अप्रैल से प्रभावी होगा और आगामी वर्ष की 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा। संयोग से, वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित सूचकांकित प्रशुल्क वर्ष 2016-17 के लिए अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि वर्ष 2016-17 के लिए सूचकांकन कारक 'शून्य' था।

- (vii) इस प्राधिकरण ने 30 जून, 2014 को सीएचपीटी द्वारा संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रस्तावित निष्पादन मानकों के साथ, दरमान अधिसूचित किए हैं। इसलिए इस प्राधिकरण द्वारा 30 जून, 2014 के आदेश में अनुमोदित निष्पादन मानकों को भी जीपीएसपीएल के प्रस्तावित दरमानों में शामिल करके अधिसूचित किया जाता है।
- (viii) 30 जून, 2014 के आदेश में यथा अनुमोदित दरमानों में दरों पर लागू अन्य सभी शासी सोपाधिकताएं निम्नलिखित के अतिरिक्त धारित की जाती है:

वीओसीपीटी द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण को देखते हुए इस प्राधिकरण ने अपने 29 सितम्बर, 2015 के आदेश सं. टीएएमपी/53/2015-वीओसीपीटी के द्वारा नौवहन महानिदेशालय की सिफारिश के आधार पर पारित किया। उस आदेश में अनुमोदित उपबंधों में 26 नवम्बर, 2015 के आदेश सं. टीएएमपी/53/2015-वीओसीपीटी द्वारा और संशोधन किया। कथित आदेश सभी महापत्तन न्यासों द्वारा समान रूप से अपनाये जाने के लिए था। उस आदेश के पश्चात पोत परिवहन महानिदेश ने 20 मई, 2016 के अपने पत्र सं. एसडी-9 सीएचएआरटी (309)/2016 ने 26 नवम्बर, 2015 के आदेश में अनुमोदित उपबंधों पर और आगे स्पष्टीकरण जारी किया। तदनुसार इस प्राधिकरण ने 26 नवम्बर, 2015 के आदेश के पैरा 9क(ii) और 10(ii) के उपबंधों में मामूली सा संशोधन करते हुए स्पष्टीकरण आदेश पारित किया। उस आदेश में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संशोधित उपबंध जीपीएसपीएल के दरमानों में

सामान्य निबंधन और शर्तों की टिप्पणी सं. (ii) के स्थान पर टिप्पणी संख्या (ii) और (iii) के रूप में अद्यतन किया जाता है। उसके बाद की टिप्पणियों की सं. को पुनः संख्याकित किया जाता है।

- (ix) जीपीएसपीएल ने अपने एक पत्र में उन्हें आबंटित बर्थों के बारे में जीपीएसपीएल ने दायर पंचाट का संकेत दिया है। विशिष्ट रूप से किए गए अनुरोध के बावजूद भी सीएचपीटी ने कोई टिप्पणी नहीं की है। तथापि, इस आदेश का प्रयोजन, जीपीएसपीएल के नाम से अधिसूचना की सीमा तक ही सीमित है। जीपीएसपीएल को आबंटित बर्थों के बारे में पंचाट का मामला सीपीएचटी और जीपीएसपीएल के बीच का आपसी मामला है न कि जीपीएसपीएल द्वारा उगाही योग्य प्रशुल्क से संबंधित है। इसलिए सूचित किये गए पंचाट से जीपीएसपीएल के नाम से दरमानों की अधिसूचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (x) जीपीएसपीएल ने अपने एक पत्र में यह भी सूचित किया है कि उसे अन्य महापत्तन न्यासों की तरह प्रयोक्ताओं से अग्रिम में एचएमसी प्रभारों की वसूली करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में सामान पर दरों के भुगतान का समय एमपीटी अधिनियम 1963 की धारा 58 द्वारा शासित होगा जो यह अनुबद्ध करता है कि उतरने वाले सामान की दरें और बोर्ड परिसर से हटाये जाने वाले सामान की दरें अथवा निर्यात के लिए पोत लदान अथवा पोतांतरण किए जाने वाले सामान के प्रभार सामान के हटाये जाने, पोत पर लदान अथवा पोतांतरण से पूर्व भुगतान किए जाने होते हैं।
- 9.1 परिणाम में और ऊपर दिए गए कारणों तथा सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण चैनई पत्तन न्यास में कार्गो प्रहस्तन प्रचालनों के लिए 100 टन हार्बर क्रेनों (एचएमसी) की आपूर्ति, प्रचालन और अनुरक्षण के दरमानों की अधिसूचना के लिए मैसर्ज ग्लोबल पोर्ट साल्यूशनज प्रा0 लि0 (जीपीएसपीएल) से प्राप्त प्रस्ताव के लिए क्रमशः **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-II** पर संलग्न दरमानों और निष्पादन मानकों की अधिसूचना को अनुमोदित करता है।
- 9.2 जीपीएसपीएल के लिए अधिसूचित दरमान जीपीएसपीएल द्वारा सीएचपीटी में प्रचालन आरंभ करने की तारीख अर्थात् 22 जून, 2015 से प्रभावी होंगे।
- 9.3 जीपीएसपीएल को निदेश दिया जाता है कि विशिष्ट बर्थों के वाणिज्यिक परिचालन के दौरान प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिन के भीतर सीएचपीटी के माध्यम से सीएचपीटी की बर्थ संख्या डब्ल्यूक्यू I, II, III और IV तथा मध्य बर्थ एसक्यू I तथा II जेडी I जेडी III व जेडी V पर पिछले 3 महीने के दौरान एचएमसी के वास्तविक और वित्तीय निष्पादन के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
- 9.4 दिशानिर्देशों के खंड 3.8.5 के अनुसार, दरमानों और सोपाधिकतओं के वितरण पर यदि कोई प्रश्न उनके स्पष्टीकरण अथवा व्याख्या के बारे में उठता है, तो मामले को इस प्राधिकरण के भेजा जाए तथा इस बारे में उसका निर्णय प्रचालक पर बाध्यकार होगा।
- 9.5 लाइसेंसधारक से प्रत्याशा की जाती है वह, कम से कम, बोली दस्तावेजों / लाइसेंस करार में दिए गए निष्पादन मानकों के अनुरूप निष्पादन करे।
- 9.6 लाइसेंसधारक का वास्तविक निष्पादन इस प्राधिकरण द्वारा अनुवीक्षण किया जाएगा। यदि सेवा की गुणता के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो यह प्राधिकरण ऐसे आरोपों की जांच करेगा और अपने निष्कर्ष सीएचपीटी को भेजेगा। यदि प्रचालक के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जानी है तो, सीएचपीटी संबंधित लाइसेंस करार के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई आरंभ करेगा।

[विज्ञापन-III /4/असाधारण/260/17]

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

अनुलग्नक-।

**ग्लोबल पोर्ट साल्यूशनज प्राइवेट लिमिटेड****चैन्नई पत्तन न्यास की बर्थ संख्या डब्ल्यूक्यू I, II, III व IV और मध्य बर्थ एसक्यू I व II जेडी 1, III और जेडी V पर हार्बर मोबाईल क्रेनों के प्रचालन हेतु दरमान****1.1 परिभाषाएं- सामान्य**

इन दरमानों में जब तक संघर्ष अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी :

- (i) 'तटीय पोत' का अर्थ है कोई पोत जो भारत में किसी पत्तन या स्थान से भारत में किसी अन्य पत्तन या स्थान के बीच व्यापार में अन्नय रूप से नियोजित है तथा जिसके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध लाइसेंस है।
- (ii) 'विदेशगामी पोत' का अर्थ है तटीय पोत के अलावा कोई अन्य पोत।
- (iii) 'दिन' का अर्थ है प्रातः 6 बजे से शुरू होकर अगले दिन के प्रातः 6 बजे तक है।
- (iv) 'एचएमसी' का तात्पर्य परियोजना हेतु बीओओ द्वारा आपूर्ति की गई हार्बर मोबाईल क्रेन है।
- (v) 'टन' का अर्थ एक मीट्रिक टन या 1000 किलोग्राम है।

**1.2 सामान्य निबंधन और शर्तें**

- (i) (क). कूड के अलावा सभी तटीय कार्गो के लिए कार्गो संबंधित प्रभार पीओएल, लौह अयस्क, लौह पैलेट्स और थर्मल कोयले सहित, सामान्य कार्गो संबंधी प्रभारों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।  
(ख). कार्गो संबंधी प्रभारों के मामले में, पोत तट स्थानांतरण हेतु रियायती दरें सभी संगत प्रभारों पर लगाई जारी चाहिए।  
(ग). तटीय कार्गो जलयानों हेतु प्रभार भारतीय रु. में मूल्यवर्गित होंगे और लिए जाएंगे।
- (ii) सीमा शुल्क अथवा पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा निर्धारित पोत की हैसियत पोत संबंधित प्रभारों की वसूली के प्रयोजन के लिए 'तटीय' अथवा 'विदेशगामी' रूप में इसके वर्गीकरण के लिए निर्णायक कारक होगा और कार्गो की प्रकृति अथवा इसका मूल इस प्रयोजन के लिए कोई प्रासंगिक नहीं होगा।
- (iii) पोत संबंधी प्रभारों (वीआरसी) की उगाही के लिए पोत के वर्गीकरण की प्रणाली :  
(क) ऐसे पोत जो सीमा शुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर भारतीय पत्तन के अपने प्रथम पत्तन पर तटीय गमन के लिए परिवर्तित होते हैं, उन्हें तब तक और किसी अन्य सीमा शुल्क परिवर्तन आदेश की आवश्यकता नहीं है जब तक वे भारतीय तट पर गमन करते हैं।  
(ख) विदेशी ध्वज का विदेशगामी पोत नौवहन महानिदेशक से विशिष्ट अवधि लाइसेंस और सीमा शुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय गमन के लिए परिवर्तित हो सकते हैं।
- (iv) रियायती तटीय दर और विदेशी दर पर पोत संबंधी प्रभारों (वीआरसी) की उगाही के लिए मानदंड  
(क) ऐसे परिवर्तन के मामलों में, लदान पत्तन द्वारा तटीय दरें पोत के तटीय सामानों की लदाई शुरू किए जाने के समय से प्रभावी होंगी।  
(ख) ऐसे परिवर्तन के मामलों में, तटीय दरें केवल पोत द्वारा तटीय कार्गो उतराई प्रचालनों को पूरा किए जाने तक प्रभावी होंगी, उसके तत्काल पश्चात् विदेशगामी दरें उतराई पत्तनों द्वारा प्रभावी होंगी।



- (ग) नौवहन महानिदेशक से तटीय लाइसेंस वाले विनियुक्त भारतीय तटीय पोतों के लिए, तटीय दरों की पात्रता के लिए कोई अन्य दस्तावेज अपेक्षित नहीं होंगे।
- (v) रियायती तटीय दर पोत संबंधी प्रभारों (वीआरसी) की उगाही के लिए मानदंड
- (क). 'विश्वभर और तटीय' परिचालन के लिए भारतीय सामान्य व्यापारिक लाइसेंस धारक विदेशगामी भारतीय पोत को प्रहस्तन प्रभारों (एचसी) के संदर्भ में लागू तटीय दरें प्रभारित होंगी अर्थात् निम्नलिखित परिदृश्य में घाट शुल्क सहित जलयान से तट तक स्थानांतरण और क्वे से / को भंडार यार्ड से / को अंतरण।
- (i). तटीय गमन के लिए परिवर्तित और किसी भारतीय पत्तन से किसी अन्य भारतीय पत्तन को तटीय सामान ढोना।
- (ii). तटीय गमन के लिए परिवर्तित नहीं परंतु किसी भारतीय पत्तन से किसी अन्य भारतीय पत्तन को तटीय सामान ढोना।
- \* केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड का 25 फरवरी, 2002 का परिपत्र सं. 15/2002 सीयूएस भारतीय ध्वज के विदेशगामी पोत को बिना किसी सीमा शुल्क परिवर्तन आदेश के किसी भारतीय पत्तन से किसी अन्य भारतीय पत्तन को तटीय सामान ढोने की अनुमति देता है।
- (ख) विदेशी ध्वज का पोत पोतपरिवहन महानिदेशक से विशिष्ट अवधि लाइसेंस और सीमा शुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय गमन के लिए परिवर्तन के मामले में ऐसे पोत द्वारा किसी भारतीय पत्तन से किसी अन्य भारतीय पत्तन को तटीय सामान / कंटेनर ढोने पर तटीय सामान / कंटेनर के लिए लागू तटीय दरें उगाही जाएंगी।
- (vi) **विलंबित भुगतानों / वापसियों पर ब्याज :**
- (क). प्रयोक्ता को दरमानों के अधीन विलंबित भुगतानों पर दंडात्मक ब्याज अदा करना होगा। उसी प्रकार से, टर्मिनल आपरेटर, विलंबित वापसियों पर दंडात्मक ब्याज अदा करेगा।
- (ख). दंडात्मक ब्याज की दर, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा घोषित आधार पर से 2 प्रतिशत अधिक होगी। दंडात्मक ब्याज की दर, टर्मिनल आपरेटर एवं प्रयोक्ता दोनों पर समान रूप से लागू होगी।
- (ग). वापसियों में विलंब की गिनती, सेवाओं के पूरा होने की तारीख से केवल 20 दिनों तक अथवा प्रयोक्ताओं से अपेक्षित सभी दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर, उनमें से जो भी बाद में हो, कि जाएगी।
- (घ). प्रयोक्ता द्वारा भुगतान में विलंब की गणना, टर्मिनल ऑपरेटर द्वारा बिलों को प्रस्तुत करने की तारीख के बाद केवल 10 दिन की, की जाएगी। तथापि, यह उपबंध उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां भुगतान सेवाएं प्राप्त करने से पूर्व कर दिया जाता है जहां दरमानों में एक शर्त के रूप में प्रभारों का भुगतान अग्रिम में करना निर्धारित है।
- (vii). निकाले गए सभी प्रभार बिल के कुल योग पर अगले रुपये में पुर्णांकित किये जायेंगे।
- (viii). वापसी के किसी भी दावे पर तभी विचार किया जाएगा यदि वापसी 100 रु. अथवा अधिक हो। इसी प्रकार, एचएमसी प्रचालक कम संग्रहण पर अनुपूरक बिल नहीं बनाएगा यदि टर्मिनल प्रचालक को देय राशि 100/- रु. से कम है।
- (ix) (क) इस दरमानों में निर्धारित दरें उच्चतम दरें अधिकतम स्तर पर हैं, इसी प्रकार कटौती और छूट जमीनी स्तर पर हैं। एचएमसी प्रचालक यदि चाहे तो निम्न दरें ले सकता है और / अथवा अधिक छूट अनुमत कर सकता है।

- (ख) एचएमसी प्रचालन यदि चाहे तो मान दरों में निर्धारित दरों की अनुप्रयोक्ता को शासित करने वाली निर्धारित शर्तों का पुनर्गठन कर सकता है, यदि ऐसे पुनर्गठन से प्रयोक्ता को प्रति यूनिट दर में राहत मिले और मानदरों में निर्धारित यूनिट दरें अधिकतम स्तर से न बढ़ें।
- (ग) बशर्ते कि एचएमसी प्रचालन जनता को ऐसी निचली दरें और / अथवा ऐसी दरों की अनुप्रयोगिता को शासित करने वाली शर्तों को जनता को अधिसूचित करेगा और ऐसी निचली दरों में किसी परिवर्तन और / अथवा ऐसी दरों की अनुप्रयोगिता को शासित करने वाली शर्तों को जनता को अधिसूचित करता रहेगा बशर्ते कि नई निर्धारित दरें प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित दरों से अधिक नहीं होगी।
- (ख) बीओओ प्रचालन की वजह से न्यायसंगत विलंब के इतर प्रयोक्ता को विलंब हेतु प्रभार नहीं देने होंगे। यदि पोत खराबी के कारण अथवा एमएमसी के बीओओ प्रचालक की अनुपलब्धता अथवा बीओओ प्रचालक की वजह से खड़ा रहता है तो बीओओ प्रचालक चैन्नई पल्ल न्यास को देय बर्थ किराए के समकक्ष छूट (चैन्नई पल्ल न्यास की वर्तमान मानदरों के अनुसार) जलयान के खड़े रहने की अवधि के दौरान उपार्जित छूट दे सकता है।

## 2. 100 टन हार्बर मोबाईल क्रेन क प्रयोगार्थ संचालन प्रभार :

क्र.सं.	कार्गो की किस्म	विदेशी रु.	तटीय रु.
1	शुष्क बल्क कार्गो (उर्वरक के साथ)	47.91	28.74
2	स्टील और बोराबंद कार्गो	99.81	59.89
3	अन्य ब्रेक बल्क कार्गो	159.70	95.82

**टिप्पणी:** शुल्क बल्क कार्गो, स्टील और बोराबंद कार्गो और अन्य ब्रेक बल्क कार्गो के संबंध में प्रति टन प्रहस्तन प्रभार पोत से समुद्र तट तक ग्रेव का प्रयोग करते हुए और विलोमतः के संबंध में है।

## 3. 100 टन हार्बर मोबाईल क्रेन के प्रयोगार्थ विविध प्रभार :

क्र.सं.	कार्गो की किस्म	विदेशी रु.	तटीय रु.
1	शुष्क बल्क कार्गो (उर्वरक के साथ)	0.98	0.58
2	स्टील और बोराबंद कार्गो	2.04	1.22
3	अन्य ब्रेक बल्क कार्गो	3.26	1.96

**टिप्पणी:** शुल्क बल्क कार्गो, स्टील और बोराबंद कार्गो और अन्य ब्रेक बल्क कार्गो के संबंध में प्रति टन प्रहस्तन प्रभार कार्गो के पोत के भीतर स्थानांतरण के संबंध में है।

## 4. उपरोक्त अनुसूची (2) की सामान्य टिप्पणी

- (i) ग्लोबल पोर्ट साल्यूशनज प्रा. लि. के दरमानों में प्रशुल्क कैप को मुद्रास्फिति से सूचकांकन किया जाएगा किंतु 1 जनवरी, 2015 और संगत वर्ष की 1 जनवरी के बीच होने वाले थोक मूल्य सूचकांक में भिन्नता के 60 प्रतिशत की सीमा तक ही होगा। प्रशुल्क कैप का स्वतः समायोजन प्रतिवर्ष किया जाएगा और समायोजित प्रशुल्क कैप संगत वर्ष के 1 अप्रैल से आगामी वर्ष की 31 मार्च तक प्रभावी होगा।
- (ii) वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) की तारीख से उसी वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक, प्रशुल्क उस वर्ष के सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क तक सीमित रहेगा, जो अधिकतम होगा। उक्त संदर्भ प्रशुल्क सूचकांकन के आधार पर प्रति वर्ष स्वतः ही

संशोधित होना चाहिए, जैसा कि प्रशुल्क दिशानिर्देशों, 2013 के पैरा 2.2 में उपबंधित है और जो पूरी लाइसेंस अवधि के लिए लागू रहेगा।

तथापि, जीपीएसपीएल प्रचालन के दूसरे वर्ष से आगामी वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से कम से कम 90 दिन पूर्व संगत वित्तीय वर्ष के सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क के अतिरिक्त निष्पादन मानक ("निष्पादन संबद्ध प्रशुल्क") के साथ-साथ प्रशुल्क प्रस्ताव करने को स्वतंत्र होगा। ऐसा निष्पादन आधारित प्रशुल्क उस संगत वर्ष के सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क के 15% से अधिक नहीं होगा (और यह अधिकतम प्रशुल्क होगा)। निष्पादन आधारित प्रशुल्क अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के पहले दिन से प्रभावी होगा और पूरे वित्तीय वर्ष में प्रभावी रहेगा।

- (iii). प्रस्ताव, लाइसेंस करार में यथासमाविष्ट 12 महीने की पिछली अवधि अथवा प्रचालन के प्रथम वर्ष के वास्तविक महीनों की संख्या जैसा भी मामला हो, निष्पादन मानक की उपलब्धि दर्शाते हुए परियोजना के रियायत करार के अंतर्गत नियुक्त स्वतंत्र अभियंता से एक प्रमाण-पत्र के साथ प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (iv). प्रस्ताव की प्राप्ति पर, प्राधिकरण प्रस्ताव की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर निष्पादन मानक की उपलब्धि के बारे में महापत्तन न्यास की राय मांगेगा जैसा प्रशुल्क दिशानिर्देश 2013 के पैरा 5 में दिया गया है।
- (v). यदि जीपीएसपीएल पिछले 12 महीनों में लाइसेंस करार के अनुसार निष्पादन मानक प्राप्त नहीं कर पाता, तो प्राधिकरण आगामी वित्तीय वर्ष के लिए निष्पादन आधारित प्रशुल्क को अधिसूचित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगा और जीपीएसपीएल केवल आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लागू सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क का पात्र होगा।
- (vi). महापत्तन न्यास की राय पर विचार करने के पश्चात्, यदि प्राधिकरण संतुष्ट हो जाता है कि, रियायत करार में यथानिर्दिष्ट निष्पादन मानक प्राप्त कर लिये गए हैं, तो यह आगामी वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से लागू निष्पादन आधारित प्रशुल्क को मार्च की 15 तारीख तक अधिसूचित करेगा।
- (vii). निष्पादन आधारित प्रशुल्क के प्रस्ताव पर सुविचार करते समय, प्राधिकरण निष्पादन मानकों और जीपीएसपीएल द्वारा उनके अनुपालन को ध्यान में रखेगा। प्राधिकरण लाइसेंस द्वारा निष्पादन मानकों की प्राप्ति अथवा अन्यथा के आधार पर निष्पादन आधारित प्रशुल्क को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का निर्णय लेगा। सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क और निष्पादन आधारित प्रशुल्क का निर्धारण प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2013 में संलग्न परिशिष्ट में दिखाये गए उदाहरण के अनुसार किया जायेगा।
- (viii). प्रचालन के तृतीय वर्ष से, निष्पादन आधारित प्रशुल्क का जीपीएसपीएल का प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा स्वतः अधिसूचित किया जायेगा बशर्ते स्वतंत्र अभियंता द्वारा यथाप्रमाणित पिछले 12 महीनों में निष्पादन मानक प्राप्त कर लिए हों। लाइसेंसी, तीसरे वर्ष से, निष्पादन आधारित प्रशुल्क के लिए निष्पादन आधारित प्रशुल्क प्रस्ताव, स्वतंत्र अभियंता से उपलब्धि प्रमाण-पत्र के साथ, पहली मार्च तक प्रस्तुत करेगा और प्राधिकरण आगामी वित्तीय वर्ष से प्रभावी निष्पादन आधारित प्रशुल्क को 20 मार्च तक अधिसूचित कर देगा।

\*\*\*\*\*

अनुलग्नक- II

**ग्लोबल पोर्ट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड**

**निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन (बीओओ) आधार पर पीपीपी मोड के अंतर्गत चैन्नई पत्तल में हार्बर मोबाईल क्रेनों की आपूर्ति, अनुरक्षण और प्रचालन हेतु परियोजना के लिए निष्पादन मानक**

**निष्पादन मानक**

छूटग्राही कार्गो के प्रतिदिन (वास्तविक कार्यकारी 24 घंटे) प्रति हार्बर मोबाईल क्रेन (एमएमसी) अथवा वास्तविक कार्यकारी आनुपातिक घंटों की टनभार निम्नानुसार है।

**(क) शुष्क बल्क कार्गो के लिए**

12500 मीट्रिक टन (औसतन) प्रतिदिन प्रति एचएमसी अथवा समकक्ष क्रेन

**(ख) स्टील और बैग्ड कार्गो के लिए**

स्टील और बैग्ड कार्गो- 6000 मीट्रिक टन (औसतन) प्रति घंटा प्रति एचएमसी अथवा समकक्ष क्रेन

**(ग) ब्रेक बल्क कार्गो के लिए**

अन्य 3750 मीट्रिक टन (औसतन) प्रति घंटा प्रति एचएमसी

\*\*\*\*

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS****NOTIFICATION**

Mumbai, the 29th September, 2017

**No. TAMP/60/2017-CHPT.**—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from M/s. Global Port Solutions Pvt. Ltd. (GPSPL) for notification of its Scale of Rates for “Supply, operate and maintenance of 100 Tonne Mobile Harbour Cranes (HMCs) for Cargo handling operations at Chennai Port Trust, as in the Order appended hereto.

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS****Case No. TAMP/60/2017-CHPT**

M/s Global Port Solutions Private Limited

-----

Applicant

**QUORUM:**

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- ((ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

**ORDER**

(Passed on this 15<sup>th</sup> day September of 2017)

This case relates to a proposal received from M/s. Global Port Solutions Pvt. Ltd. (GPSPL) for notification of its Scale of Rates for “Supply, Operate and Maintenance of 100 T Mobile Harbour Cranes (HMCs) for Cargo handling operations at Chennai Port Trust (CHPT).

- 2.1. Based on the proposal filed by the CHPT for fixation of Reference tariff for supply, maintenance and operation of HMCs at Berth Nos.WQ-I, II, III & IV and Center Berth, SQ-I & II, JD-I, JD III and JD-V at CHPT, this Authority vide its Order No. TAMP/20/2014-CHPT dated 30 June, 2014 had approved the reference Scale of Rates (SOR) under the Tariff Guidelines of 2013.

- 2.2. As per Section 48 read with Section 42(4) of the Major Port Trusts (MPT) Act, 1963, any person authorized by the Major Port Trust to render services can levy tariff based on the Scale of Rates approved and notified by this Authority in the name of such authorized person.
- 3.1. During correspondence with CHPT on some other matter, it came to our notice that CHPT has already authorized an Operator to provide the services of HMCs at CHPT. The said Operator had not approached this Authority for notification of Scale of Rates (SOR) in its name. Accordingly, the CHPT (being the Licensor) was requested vide our letter No. TAMP/52/2007-CHPT dated 07 June, 2017 to inform the concerned operator to file an appropriate proposal for notification of SOR in its name, before this Authority.
- 3.2. The CHPT vide its letter No. MEE/MI/024/2014/Dy.CME (R&D) dated 20 June, 2017 has requested Global Port Solutions Private Limited (GPSPL) to file a proposal for notification of Scale of Rates in its name.
- 3.3. In response, the GPSPL vide its letter dated 22 June, 2017 requested this Authority to expedite the revision of schedule of rates for supply, operation and maintenance of mobile harbour crane at CHPT, considering that 3 months of current financial year has already lapsed. It has also stated that any delay in the revision of rates may cause huge financial burden on them and they may not be in a position to levy additional tariff, if any, after completion of the work and billing.
- 3.4. Subsequently, the GPSPL vide its letter dated 11 July, 2017 has made the following submissions:
- (i). As per the Order given, the Concessionaire is to collect the charges in advance like any other port charges for deploying MHCs, which is a regular practice in other major ports.
  - (ii). However, the GPSPL has been experiencing difficulties in realizing the MHC charges from customers and CHPT is not interfering in the matter.
  - (iii). The matter is generally in line with the agreement made between CHPT and GPSPL under Public-Private Partnership scheme.
  - (iv). Moreover, GPSPL has to pay interest (bank rate + 2%) on delayed port revenue share as per agreement.
  - (v). It is requested to issue revised Schedule of rates for HMC charges for the year 2017-18.
- 3.5. Further, the GPSPL vide its e-mail dated 18 July, 2017 has stated that the GPSPL has an arbitration filed with the CHPT with respect to the berths which are allotted and that as per the interim arbitration order, the GPSPL is allowed to handle cargoes in JD 2, 4 and 6.
- 4.1. The GPSPL did not furnish full-fledged draft Scale of Rates (SOR) along with the conditionalities governing the levy of proposed rates as notified in the Reference Tariff Order of June, 2014, to be notified in its name. The GPSPL had also not furnished the Completion Certificate from Independent Engineer. Accordingly, we have vide our letter dated 28 July 2017 requested GPSPL to furnish complete proposal along with Scale of Rates and conditionalities and a copy of completion certificate of the project from the independent Engineer, to us and to the Licensor Port, CHPT.
- 4.2. Simultaneously, the CHPT was also requested vide our letter dated 28 July, 2017 to furnish its comments to us on the information/ documents to be furnished by GPSPL. Also, a copy of the GPSPL e-mail dated 18 July, 2017 was forwarded to CHPT for its comments. However, the CHPT did not respond till the case was finalized.
- 5.1 In response to our letter dated 28 July, 2017, the GPSPL vide its email dated 1 August, 2017 has made the following submissions:
- (i). The tender for Supply, Operation and Maintenance of 100 tons Harbour Mobile cranes at CHPT was awarded to the consortium of Roadwings International Private Limited and Apana Logistics Pvt. Limited, which formed a Special Purpose Vehicle (SPV) named Global Port Solutions Pvt. Limited.
  - (ii). Based on the letter received from CHPT earlier, the rates were indexed by 2.29% in accordance with TAMP letter dated 08 April, 2015.

- (iii). The rates with 2.29% indexation are still being continued to be charged as on date by GPSPL, as given below:

Handling Charges per ton for the use of 100 ton Mobile Crane at CHPT.

Sl. No.	Type of Cargo	Foreign ₹.	Coastal ₹.
1	Dry Bulk Cargo	47.91/-	28.74/-
2	Steel and Bagged Cargo	99.81/-	59.89/-
3	Other Break Bulk Cargo	159.69/-	95.82/-

Miscellaneous Charges per ton for use of 100 ton Mobile Cranes at CHPT

Sl. No.	Type of Cargo	Foreign ₹.	Coastal ₹.
1	Dry Bulk Cargo	0.98/-	0.58/-
2	Steel and Bagged Cargo	2.04/-	1.22/-
3	Other Break Bulk Cargo	3.26/-	1.95/-

- (iv). It is requested to index the scale of rates based on the WPI which shall be applicable for the Harbour Cranes in the name of GPSPL.
- 5.2. The GPSPL has also forwarded a copy of the Commissioning Certificate issued by CHPT and Scale of Rates for the project. The Certificate issued by the CHPT states that 2 nos. of Mobile Harbour Cranes were commissioned on 15 June, 2015 and the Cranes were put into operation on 22 June, 2015 after issuing of Trade Notice.
6. The Case has been examined based on the information made available by the GPSPL.
- 7.1. Clause 2.9.1. of the Tariff Guidelines of 2008 for fixation of upfront tariff stipulates that private operator shall approach this Authority for notification of Scale of Rates containing ceiling rates applicable to his operations before commencement of commercial operations as required under Section 48 of MPT Act and as per Clause 2.9.2. of tariff guidelines of 2008, the Scale of Rates to be framed by TAMP shall be in line with the tariff caps prescribed for the port and included in the bid document subject to indexation explained in Clause 2.8. Such Scale of Rates and statement of conditions shall be notified by this Authority in the Gazette of India as required by the Major Port Trusts Act, 1963.
- 7.2. While clause 2.9.1 of the Upfront Tariff Guidelines of 2008 explicitly stipulates that before commencement of commercial operation, the private operator shall approach TAMP for notification of the Scale of Rates as required under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963, such an explicit provision is not available in the Tariff Guidelines of 2013.
- 7.3. As per Section 48 read with Section 42(4) of the Major Port Trusts (MPT) Act, 1963, any person authorised by the Major Port Trusts to render services can levy tariff based on the Scale of Rates (SOR) notified by this Authority. That being so, the BOT operators governed under the tariff guidelines 2013 who have been authorised by Major Port Trust under Section 42(3) of the MPT Act 1963, need to get the indexed SOR notified in their name well before the commencement of operations.
- 7.4. As per clause 4.2 of the Reference Tariff Guidelines of 2013, the Tariff Caps are to be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January, 2008 and 1 January of the relevant year, and the adjusted tariff will come into force from 1 April of the relevant year to 31 March of the following year.
- 7.5. As per clause 3 [General note to Schedule (2)] in the reference tariff for operating Harbour Mobile Cranes at Berths no. WQ I, II, III & IV and Centre Berth SQ I & II, JD I, JD III and JD V of Chennai Port Trust approved by this Authority vide Order No. TAMP/20/2014-CHPT dated 30 June 2015, tariff caps will be indexed to inflation to an extent of 60% of the variation in the WPI occurring between 1 January, 2014 and 1 January of the relevant year.

- 7.6. The base year for the reference tariff and the corresponding annual escalation for the year 2014-15, 2015-16, 2016-17 and 2017-18 has been announced by this Authority and communicated to all the Major Port Trusts including CHPT. Accordingly, the annual indexation factor announced by this Authority is as under:

Year	Annual Indexation Factor
2014-15	3.78%
2015-16	2.29%
2016-17	NIL
2017-18	1.20%

- 7.7. Thus in short, the GPSPL has come up after commencement of commercial operation on 22 June 2015, for notification of Scale of Rates in its name.

8. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i). This Authority has passed an Order No. TAMP/20/2014-CHPT dated 30 June 2014 fixing reference tariff based on the proposal filed by the CHPT for supply, maintenance and operation of HMCs at Berth Nos. WQ-I, II, III & IV and Center Berth, SQ-I & II, JD-I, JD III and JD-V at Chennai Port Trust (CHPT). The said Order was notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 31 July 2014 vide Gazette No.230.
- (ii). The CHPT has awarded the project of supply, maintenance and operation of HMCs at Berth Nos. WQ-I, II, III & IV and Center Berth, SQ-I & II, JD-I, III and JD-V at CHPT to the consortium of Roadwings International Pvt. Ltd. and Apana Logistics Pvt. Ltd. which formed an SPV named Global Port Solutions Pvt. Ltd. (GPSPL). The CHPT has entered into an Agreement with GPSPL on 31 August 2015 for a period of 10 years.
- (iii). As brought out earlier, as per Section 48 read with Section 42(4) of the Major Port Trusts (MPT) Act, 1963, the Scale of Rates leviable by any person authorised by the Major Port Trusts to render services requires to be notified by this Authority. That being so, the BOT operators governed under the tariff guidelines 2013 who have been authorised by Major Port Trust under Section 42(3) of the MPT Act 1963, need to get the indexed SOR notified in their name well before the commencement of operations. The GPSPL has approached this Authority with a request to notify the Scale of Rates in its name, though after commencement of its commercial operation on 22 June 2015.
- (iv). The GPSPL in its various communications to us has expressed urgency to have the rates notified in their name, presumably hinting that there has been a delay on the part of this Authority to notify the Scale of Rates in the name of GPSPL. In this regard, it is to state that after passing of the Order in June 2014, the Licensor port CHPT would have entered into a Concession Agreement with GPSPL. Before commencement of operations in June 2015, the GPSPL should have approached this Authority for notification of the Scale of Rates in its name, keeping in view the statutory provisions. This Authority was not aware earlier, about the CHPT entering into a Concession Agreement with GPSPL for operation of HMCs. However, immediately, when the matter came to our notice, steps have been taken in the direction to enable notification of the Scale of Rates in the name of the GPSPL.
- (v). Though the CHPT has not responded on the proposal of the GPSPL, it is seen from the copy of the documents furnished by GPSPL, that the CHPT has informed to GPSPL that 2 nos. of HMCs were commissioned on 15 June 2015 and the cranes were put into operation on 22 June 2015. The Concession Agreement entered between CHPT and GPSPL as forwarded by CHPT earlier, does not mention about issue of Independent Engineer's Certificate on completion of project. As per the Concession Agreement, the Concessionaire has brought two numbers of HMCs to CHPT and the cranes are ready for operation. The GPSPL has made available the 2 nos. of 'Report of Commissioning of HMC' issued in May 2015 by a third party which assures of the stability of both the Cranes. The tariff effective date to be considered accordingly i.e. 22 June 2015.

The GPSPL in its proposal has sought notification of SOR but has not indicated its effective date for implementation of SOR. If reference tariff is notified from 1 April 2017, the tariff collected by GPSPL from 22 June 2015 till 1 April 2017 will not have any approval of this Authority. As per the statute, the operator authorised by the port can collect the tariff for services rendered by them only upon notification of Scale of Rates by this Authority. The GPSPL did not approach this Authority in

June 2015 for notification of SOR in their name. As per CHPT Letter no.MEE/MI0214/2014/Dy.CME (R&D) dated 09 June 2015, a copy of which was made available by the GPSPL under cover of its e-mail dated 01 August 2017, the CHPT has conveyed the indexed Scale of Rates to GPSPL.

It is now, in August 2017, GPSPL has furnished complete proposal with proposed SOR for notification of SOR in its name. Since the CHPT has certified that the HMCs were put into operation on 22 June 2015, it is appropriate to consider the effective date of tariff as 22 June 2015. In view of the position brought out above, the SOR is notified to take effect from the date the GPSPL commenced the operations i.e. 22 June 2015 taking the reference tariff approved in the Order dated 30 June 2014 as base subject to the applicable WPI escalation announced by this Authority.

- (vi). (a). With reference to the indexation of the reference tariff fixed vide Order dated 30 June 2014, it is relevant here to mention that para 10.1 of the reference tariff Order no. TAMP/20/2014-CHPT dated 30 June 2014 passed by this Authority and the General Note no.4 in the Scale of Rates (SOR) approving the reference tariff, state that the tariff caps will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2014 and 1 January of the relevant year. The general note explicitly states that the base year for WPI escalation has to be 1 January 2014.
- (b). The applicable escalation factor to be applied on the base tariff of 2014 to arrive at the indexed SOR as on 22 June 2015 is 2.29%. The said indexed and notified SOR will be applicable for the year 2015-16 w.e.f. 22 June 2015. For the subsequent years as well, the said tariff will be automatically indexed to the extent of 60% of the WPI announced / to be announced by this Authority annually. The General note no. 4 of the proposed Scale of Rates retaining the general note approved in the Order dated 30 June 2014 is, therefore, suitably modified clarifying this position.

Thus, in short, for the year 2016-17 and onwards, the General Note 4 of the SoR approved by this Authority in June 2014 already prescribes automatic tariff adjustment to be made in the tariff caps every year and adjusted tariff caps will come into effect from 1 April on the relevant year to 31 March of the following year. Incidentally, the indexed tariff prescribed for the year 2015-16 will remain unaltered for the year 2016-17 since the indexation factor was “nil” for the year 2016-17.

- (vii). This Authority vide Order dated 30 June 2014 has notified the SOR alongwith Performance Standard as proposed by CHPT as per the Reference Tariff Guidelines. Therefore, the performance standard as approved by this Authority in the Order dated 30 June 2014 is also included in the proposed SOR of GPSPL and notified.
- (viii). All the other conditionalities governing the application of the rates as approved in the Scale of Rates of the Order dated 30 June 2014 are retained subject to the following.
  - (a). This Authority, in view of the clarification sought by the V.O. Chidambaranar Port Trust regarding levy of concessional charges for coastal cargo / container has passed an Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 29 September 2015 based on the recommendations of Directorate General (DG) Shipping. The provisions approved in the said Order were further amended vide Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 26 November 2015. The said Order passed is for common adoption by all the Major Port Trusts. Subsequent to the said Order, the DG Shipping vide its letter no.SD-9 CHART(309)/2016 dated 20 May 2016 has issued further clarification on the provision approved in the 26 November 2015 Order. This Authority has accordingly passed a clarificatory Order slightly amending the provision prescribed in para 9A (ii) and 10(ii) of the Order dated 26 November 2015. The amended provisions approved by this Authority in the said Order has been updated accordingly, in the Scale of Rates of GPSPL as note no. (ii) and (iii) in place of note no. (ii) under General terms and conditions. The subsequent note nos. are consequently renumbered.
- (ix). The GPSPL, in one of its correspondences, has indicated about an arbitration filed by GPSPL with regard to berths allotted to them. In spite of a specific request, the CHPT has not furnished its comments. Nevertheless, the purpose of this Order is to the limited extent of notification of Scale of Rates (SOR) in the name of GPSPL. The Arbitration regarding allotment of berths to GPSPL is a matter concerning between the GPSPL and CHPT and not reported to be on the tariff leviable by the



GPSPL. Therefore, the reported arbitration would not have a bearing on the notification of the Scale of Rates (SOR) in the name of GPSPL.

- (x). The GPSPL, in one of its correspondences has also reported the difficulties being faced by it in realizing HMC charges in advance from users unlike the position in other Major Port Trusts. In this regard, the time for payment of rates on goods will be governed by Section 58 of the MPT Act, 1963, which stipulates that rates in respect of goods to be landed shall be payable immediately on the landing of the goods and rates in respect of goods to be removed from the premises of a Board, or to be shipped for export, or to be transhipped, shall be payable before the goods are so removed or shipped or transhipped.

9.1. In the result, and for the reasons given above, and based on the collective application of mind, this Authority approves notification of Scale of Rates and Performance Standards for the Supply, operate and maintenance of 100 T Mobile Harbour Cranes (100 MT) for Cargo handling operations at berth Nos. WQ-I, II, III & IV and Center Berth, SQ-I & II, JD-I, JD III and JD-V at CHPT in the name of GPSPL operating at CHPT attached as **Annex- I** and **Annex- II** respectively.

9.2. The Scale of Rates notified for GPSPL is deemed to have come into force from the date of commencement of operations by GPSPL at CHPT i.e. from 22 June 2015.

9.3. During the commercial operation at the specified berths, within 15 days from the end of every quarter, the GPSPL is directed to submit to this Authority through the CHPT, a report containing the physical and financial performance of HMC's at Berth Nos. WQ-I, II, III & IV and Center Berth, SQ-I & II, JD-I, JD III and JD-V at CHPT during the preceding three months.

9.4. As per clause 3.8.5 of the guidelines, if any question arises requiring clarifications or interpretation of the Scale of Rates and the statement of conditionalities, the matter shall be referred to this Authority and its decision in this regard will be binding on the operator.

9.5. The Licensee is expected to perform at least at the performance norms brought out in the bid document/ License agreement.

9.6. The actual performance of the Licensee shall be monitored by this Authority. If any complaint regarding quality of service is received, this Authority shall enquire into such allegation and forward its findings to the CHPT. If any action is to be taken against the operator, the CHPT shall initiate appropriate action in accordance with the provisions of the relevant Licence Agreement.

[ADVT.-III/4/Exty./260/17]

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

**Annex – I**

**GLOBAL PORT SOLUTIONS PVT. LTD.**

**SCALE OF RATES FOR OPERATING HARBOUR MOBILE CRANES AT BERTHS NO. WQ I, II, III & IV AND CENTRE BERTH SQ I & II, JD-I, III AND JD-V OF CHENNAI PORT TRUST.**

**1.1. Definitions – General**

In this Scale of Rates, unless the context otherwise requires, the following definitions shall apply:

- (i). **“Coastal vessel”** shall mean any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India having a valid coastal licence issued by the competent authority/ **Director General of Shipping**.
- (ii). **“Foreign-going vessel”** shall mean any vessel other than coastal vessel.
- (iii). **“Day”** shall mean the period starting from 6 a.m. of a day and ending at 6 a.m. on the following day.

- (iv). **“HMC”** means Harbour Mobile Crane supplied by the BOO operator for the project
- (v). **“Tonne” Shall mean one Metric Tonne or 1000 Kilograms.**

## 1.2. General Terms & Conditions

- (i).
  - (a). The cargo related charges for all coastal cargo other than crude including POL, Iron ore and Iron pellets and thermal coal should not exceed 60% of the normal cargo related charges.
  - (b). In case of cargo related charges, the concessional rates should be levied on all the relevant handling charges for ship shore transfer.
  - (c). The charges for coastal cargo vessels shall be denominated and collected in Indian rupee.
- (ii). The status of the vessel, as borne out by its certification by the Customs or the Director General of Shipping, shall be the deciding factor for its classification as ‘coastal’ or ‘foreign-going’ for the purpose of levying vessel related charges; and, the nature of cargo or its origin will not be of any relevance for this purpose.
- (iii). System of classification of vessel for levy of Vessel Related Charges (VRC)
  - (a). A foreign going vessel of Indian flag having a General Trading Licence can convert to coastal run on the basis of a Customs Conversion Order. Such vessel that converts into coastal run based on the Customs Conversion Order at her first port of call in Indian Port, no further custom conversion is required, so long as it moves on the Indian Coast.
  - (b). A Foreign going vessel of foreign flag can convert to coastal run on the basis of a Licence for Specified Period or Voyage issued by the Director General of Shipping and a custom conversion order.
- (iv). Criteria for levy of Vessel Related Charges (VRC) at Concessional Coastal rate and foreign rate:
  - (a). In cases of such conversion, coastal rates shall be chargeable by the load port from the time the vessel starts loading coastal goods.
  - (b). In cases of such conversion coastal rates shall be chargeable till the vessel completes discharging operations at the last call of Indian Port; immediately thereafter, foreign going rates shall be chargeable by the discharge ports.
  - (c). For dedicated Indian coastal vessels having a Coastal licence from the Director General of Shipping, no other document will be required to be entitled to coastal rates.
- (v). Criteria for levy of Cargo Related Charges (CRC) at Concessional Coastal rate
  - (a). Foreign going Indian Vessel having General Trading License issued for ‘worldwide and coastal’ operation should be accorded applicable coastal rates with respect to Handling Charges (HC) i.e. ship to shore transfer and transfer from/ to quay to/ from storage yard including wharfage in the following scenario:
    - (i). Converted to coastal run and carrying coastal cargo from any Indian Port and destined for any other Indian Port.
    - (ii). Not converted\* to coastal run but carrying coastal cargo from any Indian Port and destined for any other Indian Port.

\* The Central Board of Excise and Customs Circular no.15/2002-Cus. dated 25 February 2002 allows carriage of coastal cargo from one Indian port to another port in India, in Indian flag foreign going vessels without any custom conversion.
  - (b). In case of a Foreign flag vessel converted to coastal run on the basis of a Licence for Specified Period or Voyage issued by the Director General of Shipping, and a Custom Conversion Order, the coastal cargo/ container loaded from any Indian Port and destined for any other Indian Port should be levied at the rate applicable for coastal cargo/ container.

- (vi). Interest on delayed payments / refunds.
- (a). The user shall pay penal interest on delayed payments under this Scale of Rates. Likewise, the HMC operator shall pay penal interest on delayed refunds.
- (b). The rate of penal interest will be 2% above the prime lending rate of the State Bank of India.
- (c). The delay on refunds will be counted only 20 days from the day of completion of services or on production of all the documents required from the users, whichever is later.
- (d). The delay in payments by the users will be counted only 10 days after the date of raising the bills by the terminal operator. This provision shall, however, not apply to the cases where payment is to be made before availing the services where payment of charges in advance is prescribed as a condition in the scale of rates.
- (vii). All charges worked out shall be rounded off to the next higher rupee on the grand total of the bill.
- (viii). No claims for refund shall be entertained unless the amount refundable is ₹100/- or more. Likewise, the HMC operator shall not raise supplementary bills for short collection, if the amount due to the terminal operator is less than ₹.100/-.
- (ix). (a). The rates prescribed in this Scale of Rates are ceiling levels; likewise, rebates and discounts are floor levels. The HMC Operator may, if he so desires, charge lower rates and/ or allow higher rebates and discounts.
- (b). The HMC Operator may also, if he so desires, rationalize the prescribed conditionality governing the application of rates prescribed in the Scale of Rates, if such rationalization gives relief to the user in rate per unit and the unit rates prescribed in the Scale of Rates do not exceed the ceiling levels.
- (c). Provided that the HMC Operator should notify the public such lower rates and / or rationalization of the conditionality governing the application of such rates and continue to notify the public any further changes in such lower rates and / or in the conditionality governing the application of such rates, provided the new rates fixed shall not exceed the rates notified by the TAMP.
- (x). Users will not be required to pay charges for delays beyond reasonable level attributable to operator. In case a vessel idles due to breakdown or non-availability of the HMCs of Operator or any other reasons attributable to Operator, rebate equivalent to berth hire charges payable to the Chennai Port Trust (as per the prevailing scale of rates of Chennai Port) accrued during the period of idling of vessel shall be allowed by Operator.

## 2. HANDLING CHARGES FOR USE OF 100 TONNE HARBOUR MOBILE CRANES:

(Rate in ₹ per tonne)

Sl. No.	Type of Cargo	Foreign	Coastal
1.	Dry Bulk Cargo (Including Fertilizer)	47.91	28.74
2.	Steel and other bagged cargo	99.81	59.89
3.	Other Break Bulk Cargo	159.70	95.82

**Note:** The per tonne handling charges in respect of Dry Bulk cargo, Steel & Bagged Cargo and Other Break Bulk Cargo, is towards handling of cargo from ship to shore using grab and vice versa.

## 3. MISCELLANEOUS CHARGES FOR USE OF 100 TONNE HARBOUR MOBILE CRANES:

(Rate in ₹ per tonne)

Sl. No.	Type of Cargo	Foreign	Coastal
1.	Dry Bulk Cargo (Including Fertilizer)	0.98	0.59
2.	Steel and other bagged cargo	2.04	1.22
3.	Other Break Bulk Cargo	3.26	1.96

**Note:** The per tonne miscellaneous charges in respect of Dry Bulk cargo, Steel & Bagged Cargo and Other Break Bulk Cargo, is towards shifting of cargo within the vessel.

**4. GENERAL NOTE TO SCHEDULE (2) ABOVE:**

- (i). The tariff caps prescribed in the Scale of Rates of Global Port Solution Pvt. Ltd. (GPSPL) will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1<sup>st</sup> January 2015 and 1<sup>st</sup> January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff caps will be made every year and the adjusted tariff caps will come into force from 1 April of the relevant year to 31<sup>st</sup> March of the following year.
- (ii). From the date of Commercial Operation (CoD) till 31st March of the same financial year, the tariff would be limited to the indexed Reference Tariff relevant to that year, which would be the ceiling. The aforesaid Reference Tariff shall be automatically revised every year based on an indexation as provided in para 2.2 of the tariff guidelines of 2013 which will be applicable for the entire licence period.

However, the GPSPL would be free to propose a tariff along with Performance Standard (the “Performance Linked Tariff”) from the second year of operation onwards, over and above the indexed Reference Tariff for the relevant financial year, at least 90 days before the 1st April of the ensuing financial year. Such Performance Linked Tariff shall not be higher than 15% over and above the indexed Reference Tariff for that relevant financial year (and this will be the Tariff Cap). The Performance Linked Tariff would come into force from the first day of the following financial year and would be applicable for the entire financial year.
- (iii). The proposal shall be submitted to TAMP along with a certificate from the independent engineer appointed under the Concession Agreement of the Project indicating the achievement of Performance Standard in the previous 12 months as incorporated in the Licence Agreement or for the actual number of months of operation in the first year of operation as the case may be.
- (iv). On receipt of the proposal, TAMP will seek the views of the Major Port Trust on the achievement of Performance Standard as outlined in para 5 of the tariff guidelines of 2013, within 7 days of receipt.
- (v). In the event of GPSPL not achieving the Performance Standard as incorporated in the Licence Agreement in previous 12 months, TAMP will not consider the proposal for notifying the Performance Linked Tariff for the ensuing financial year and the GPSPL shall be entitled to only the indexed Reference Tariff applicable for the ensuing financial year.
- (vi). After considering the views of the Major Port Trust, if TAMP is satisfied that the Performance Standard as incorporated in the Concession Agreement have been achieved, it shall notify the performance linked tariff by 15th of March to be effective from 1st of April of the ensuing financial year.
- (vii). While considering the proposal for Performance Linked Tariff, TAMP will look into the Performance Standard and its adherence by the GPSPL. TAMP will decide on the acceptance or rejection of the Performance Linked Tariff proposal based on the achievement or otherwise of the Performance Standard by the Licensee. Determination of indexed Reference Tariff and Performance Linked Tariff will follow the illustration shown in the Appendix attached to the tariff guidelines of 2013.
- (viii). From the third year of operation, the Performance Linked Tariff proposal from the GPSPL shall be automatically notified by TAMP subject to the achievement of Performance Standard in the previous 12 months period as certified by the Independent Engineer. The Licensee, for the Performance Linked Tariff from the third year onwards, will submit the Performance Linked Tariff proposal along with the achievement certificate from the independent engineer by 1st March and TAMP shall notify by 20th March, the Performance Linked Tariff to be effective from the ensuing financial year.

## Annex – II

## GLOBAL PORT SOLUTIONS PVT. LTD

**Performance Standards for the project for Supply, Maintenance and Operation of Harbour Mobile Cranes in Chennai Port under PPP mode on Build, Own and Operate (BOO) basis**

**Performance Standards**

Concessionaire shall endeavor to handle cargo per day (24 Hrs of actual working) per Harbour Mobile Crane (HMC) or tonnage of proportionate hours of actual working as detailed below.

**a. For Dry Bulk Cargo**

12500 Metric tonnes (average)/ per day per HMC or equivalent crane

**b. For Steel and bagged Cargo**

Steel and Bagged Cargo - 6000 Metric tonnes (average)/ per day per HMC or equivalent crane

**c. For Beak bulk Cargo**

Others - 3750 Metric tonnes (average)/ per day per HMC

-----